SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

Impact Factor SJIF 2025 – 5.306

Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी तथा गरीबी - कारण, प्रभाव और समाधान

राम मिलन द्विवेदी

सह-प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

इस शोध पत्र में ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बंधित में कारण, प्रभाव तथा समाधान खोजने के बारे में अध्ययन किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहा की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्यात आज भी गांवों में निवास करती है। विकास के दावों और आर्थिक उदारीकरण के बावजूद, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी और गरीबी दो सबसे गंभीर और जटिल समस्याएं बनी हुई हैं। यह शोध पत्र ग्रामीण बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूपों (जैसे- मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी) और गरीबी के मुख्य कारणों का विश्लेषण करता है। इसके साथ ही, यह समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करता है और सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है। ग्रामीण गरीबी के प्रभाव व्यापक और बहुआयामी हैं। इससे लोगों का जीवन स्तर निम्न बना रहता है, पोषण की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग शहरों की ओर पलायन करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में भी दबाव बढ़ता है और ग्रामीण विकास प्रभावित होता है। सामाजिक असमानता, अपराध और आर्थिक अस्थिरता भी इसके दुष्परिणाम हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और फसल विविधीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। ग्रामीण लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करना और कौशल विकास कार्यक्रमों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण कदम हैं। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा बुनियादी ढांचे का विकास भी आवश्यक है।

इस संदर्भ में, ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि इनके मूल कारणों को समझकर प्रभावी समाधान खोजे जा सकें। यह शोध पत्र इन समस्याओं के कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे समावेशी और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

महत्वपूर्ण शब्द

ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी, कृषि निर्भरता, कौशल विकास, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास, पलायन आदि।

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आज भी लगभग 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है। हालांकि, बदलते आर्थिक परिदृश्य, बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह समस्या केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय विकास से भी जुड़ी हुई है जो देश की समग्र प्रगति को प्रभावित करती है। ग्रामीण बेरोजगारी का स्वरूप शहरी बेरोजगारी से भिन्न होता है। यहाँ अधिकतर लोग मौसमी या आंशिक रोजगार (अर्ध-बेरोजगारी) का सामना करते हैं, विशेषकर कृषि कार्यों में। वर्ष के कुछ महीनों में काम की उपलब्धता होती है, जबकि शेष समय में लोग बेरोजगार रहते हैं। इसके अलावा, कृषि भूमि का विभाजन, संसाधनों की कमी और आधुनिक तकनीकों का अभाव भी रोजगार के अवसरों को सीमित करते हैं। गरीबी ग्रामीण जीवन का एक प्रमुख पहलू है, जो बेरोजगारी से गहराई से जुड़ी हुई है। आय के सीमित स्रोत शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, तथा सामाजिक असमानताएँ इस समस्या को और जटिल बनाती हैं। ग्रामीण गरीबों को अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं—जैसे भोजन, वस्त्र और आवास—की पूर्ति में कठिनाई होती है।

Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित करना इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार, ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए समन्वित और सतत प्रयास आवश्यक हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके।

उद्देश्य

1. ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना।
2. इनके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. समस्या के समाधान हेतु प्रभावी उपाय सुझाना।

शोध प्रविधि

इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रविधि का उपयोग किया गया है। शोध मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जो सरकारी रिपोर्टों, जनगणना, पुस्तकों और शोध पत्रों से प्राप्त किए गए हैं। इन आँकड़ों का विश्लेषण कर ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी के कारणों, प्रभावों एवं समाधानों का अध्ययन किया गया है।

गांवों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रकार

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कई रूपों में देखने को मिलती है, जो उनकी आर्थिक संरचना और कृषि-आधारित जीवनशैली से जुड़ी होती है। प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं–

I. मौसमी बेरोजगारी- यह ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सामान्य प्रकार है। कृषि कार्य केवल कुछ विशेष मौसमों में होता है (जैसे बुवाई और कटाई), जबकि बाकी समय लोगों को काम नहीं मिलता।

II. छिपी हुई बेरोजगारी- इसमें एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। यदि कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनकी श्रम क्षमता का सही उपयोग नहीं हो रहा होता।

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor SJIF 2025 – 5.306
Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

III. अर्ध-बेरोजगारी- इस स्थिति में व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार पूरा काम या आय नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करने के बजाय केवल कुछ घंटों के लिए ही काम कर पाता है।

Iv.संरचनात्मक बेरोजगारी- यह तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है, लेकिन लोगों के कौशल उस बदलाव के अनुसार नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी और औद्योगिक विकास की कमी इसका प्रमुख कारण है।

V. खुली बेरोजगारी- जब व्यक्ति काम करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिलता, तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं।

VI. शिक्षित बेरोजगारी- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे वे बेरोजगार रह जाते हैं।

ग्रामीण बेरोजगारी के ये विभिन्न प्रकार यह दर्शाते हैं कि समस्या केवल रोजगार की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता और अवसरों की असमानता से भी जुड़ी हुई है।

ग्रामीण बेरोजगारी के मुख्य कारण- ग्रामीण बेरोजगारी भारत की एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसके पीछे कई संरचनात्मक और परिस्थितिजन्य कारण जिम्मेदार हैं। प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–

I. कृषि पर अत्यधिक निर्भरता- ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि कार्य मौसमी होता है। वर्ष के कुछ महीनों में ही काम उपलब्ध होता है, जिससे शेष समय में लोग बेरोजगार रहते हैं।

II. जनसंख्या वृद्धि और भूमि का विभाजन- तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि का लगातार विभाजन हो रहा है। छोटे और सीमांत किसान पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाते, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है।

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor SJIF 2025 – 5.306
Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

III. शिक्षा और कौशल की कमी- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी के कारण लोग आधुनिक रोजगार के अवसरों के लिए योग्य नहीं बन पाते।

IV. कुटीर एवं लघु उद्योगों का अभाव- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग-धंधों की कमी के कारण कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अवसर सीमित रहते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है।

V. तकनीकी विकास का अभाव- आधुनिक तकनीकों और संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन क्षमता कम रहती है और नए रोजगार सृजित नहीं हो पाते।

VI. आधारभूत संरचना की कमी- सड़क, बिजली, पानी, परिवहन और संचार जैसी सुविधाओं की कमी के कारण उद्योगों का विकास नहीं हो पाता, जिससे रोजगार के अवसर सीमित रहते हैं।

VII . मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी- कई बार एक ही काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, जिससे वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ता, लेकिन बेरोजगारी छिपी रहती है।

VIII. सरकारी योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन- सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार योजनाएँ कई बार सही तरीके से लागू नहीं हो पातीं, जिससे उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पाता।

IX. प्राकृतिक आपदाएँ और कृषि संकट- सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ कृषि को प्रभावित करती हैं, जिससे किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं।

X. शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन- रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल का असंतुलन उत्पन्न होता है और स्थानीय विकास प्रभावित होता है।

ग्रामीण बेरोजगारी से होने वाले प्रभाव- ग्रामीण बेरोजगारी के अनेक प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते है जिनका अध्य यन निम्नउवत किया गया है-

I. आर्थिक प्रभाव- ग्रामीण बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रभाव देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो उनकी आय कम हो जाती है, जिससे गरीबी बढ़ती है। ग्रामीण परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं और कई बार उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इससे वे साहूकारों और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं

जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है। इसके अलावा, बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) घट जाती है, जिससे स्थानीय बाजारों की मांग कम हो जाती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और छिपी हुई बेरोजगारी के कारण उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और समग्र विकास की गति धीमी हो जाती है।

II. शहरी क्षेत्र की ओर पलायन- ग्रामीण बेरोजगारी के कारण लोगों को गाँवों में पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे वे बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। गाँवों में कृषि पर अधिक निर्भरता होने के बावजूद सीमित भूमि, अनियमित वर्षा और मौसमी काम के कारण पूरे वर्ष काम उपलब्ध नहीं रहता। इसी कारण युवा और श्रमिक वर्ग शहरों की ओर रुख करता है, जहाँ उद्योग, निर्माण कार्य और सेवा क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है। शहरों में अधिक आय और बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद भी पलायन को बढ़ावा देती है। शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते पलायन से शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आवास की कमी, झुग्गी-झोपड़ियों का विस्तार और बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। साथ ही, रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कई लोग कम वेतन वाले असंगठित कार्यों में लग जाते हैं। दूसरी ओर, गाँवों में काम करने योग्य लोगों की कमी हो जाती है, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास प्रभावित होता है। इस प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी के कारण पलायन गाँव और शहर दोनों के लिए कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न करता है।

III. समाजिक प्रभाव- ग्रामीण बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो उनके जीवन में निराशा और हताशा बढ़ने लगती है। इससे समाज में असंतोष की भावना पैदा होती है और कई बार अपराध, चोरी और नशे जैसी बुरी आदतों में वृद्धि देखने को मिलती है। बेरोजगारी के कारण परिवारों में तनाव बढ़ता है, जिससे सामाजिक संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा, बेरोजगारी से युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। कई युवा

Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं या शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे ग्रामीण समाज का संतुलन बिगड़ जाता है और सामाजिक असमानता बढ़ती है। धीरे-धीरे यह स्थिति समाज में अविश्वास और अस्थिरता को जन्म देती है।

IV. शिक्षा और मानव संसाधन पर प्रभाव- ग्रामीण बेरोजगारी का शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि रोजगार के अवसर कम होने से कई युवा अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं या उच्च शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पाते। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों को काम की तलाश में लगना पड़ता है। 2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आँकड़ों के अनुसार, भारत में शिक्षित बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी समस्या है, जहाँ स्नातकों में बेरोजगारी दर लगभग 11.2 प्रतिशत तक बनी हुई है, जो औसत बेरोजगारी से काफी अधिक है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक गंभीर होती है, जिससे ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास और शिक्षा का सही उपयोग नहीं हो पाता। मानव संसाधन पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव यह होता है कि देश की कार्यशील जनसंख्या का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और "मानव पूंजी" कमजोर हो जाती है। कई योग्य और शिक्षित युवा उपयुक्त रोजगार न मिलने के कारण या तो कम वेतन वाले असंगठित क्षेत्र में काम करने लगते हैं या बेरोजगार रहते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार देश में श्रम बल भागीदारी दर लगभग 59.3 प्रतिशत रही, जो बताती है कि बड़ी संख्या में लोग या तो रोजगार में नहीं हैं या सक्रिय रूप से काम नहीं पा रहे हैं। इससे देश के विकास की गति धीमी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन का सही उपयोग नहीं हो

V. कृषि क्षेत्र पर प्रभाव- ग्रामीण बेरोजगारी का कृषि क्षेत्र पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में देखने को मिलता है। जब गाँवों में अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं होते, तो अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से उनकी आवश्यकता नहीं होती। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार ग्रामीण कार्यबल का लगभग 57.7 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत पाया गया, जो यह दर्शाता है कि भारत में कृषि अब भी सबसे बड़ा

रोजगार स्रोत है, लेकिन इसमें उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। इससे खेतों में श्रम का अति-उपयोग होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन घट जाता है, जिससे कृषि आय पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा, बेरोजगारी के कारण कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और यंत्रीकरण को अपनाने की गति भी धीमी हो जाती है। अधिक श्रमिक उपलब्ध होने से किसान मशीनों की बजाय मानव श्रम पर निर्भर रहते हैं, जिससे उत्पादकता और दक्षता प्रभावित होती है। साथ ही, कम आय और रोजगार अस्थिरता के कारण किसान नई तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाओं में निवेश नहीं कर पाते। इससे कृषि विकास की गति धीमी हो जाती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था लंबे समय तक कमजोर बनी रहती है।

VI. राजनीतिक प्रभाव- ग्रामीण बेरोजगारी का राजनीतिक प्रभाव सबसे पहले सरकारी नीतियों और चुनावी मुद्दों पर दिखाई देता है। जब बड़ी संख्या में लोग रोजगार की कमी से प्रभावित होते हैं, तो रोजगार और विकास सरकार की प्राथमिक राजनीतिक मांग बन जाते हैं। 2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर लगभग 3.1 प्रतिशत के आसपास रही, लेकिन ग्रामीण युवाओं में यह दर अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या असमान रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इस कारण राजनीतिक दल ग्रामीण रोजगार योजनाओं, जैसे मनरेगा और कौशल विकास कार्यक्रमों को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल करते हैं। दूसरे, ग्रामीण बेरोजगारी के कारण सामाजिक असंतोष और आंदोलनों में वृद्धि देखी जाती है, जो राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। बेरोजगार युवा कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, धरना और आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण लोग वोटिंग व्यवहार में भी परिवर्तन करते हैं और विकास एवं रोजगार देने वाली नीतियों को अधिक समर्थन देते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी राजनीति को सीधे प्रभावित कर

VII. विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव- ग्रामीण बेरोजगारी का दीर्घकालिक प्रभाव देश के समग्र आर्थिक विकास पर बहुत गहरा पड़ता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार नहीं होता, तो

बड़ी जनसंख्या की उत्पादक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इससे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की गति धीमी हो जाती है और ग्रामीण-शहरी विकास के बीच असमानता बढ़ती है। 2025-26 के श्रम आँकड़ों के अनुसार भारत की श्रम बल भागीदारी दर श्रम बल भागीदारी दर लगभग 59 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, जिसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में कार्यशील लोग या तो रोजगार से बाहर हैं या पूरी तरह उत्पादक कार्यों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यह स्थिति दीर्घकाल में मानव संसाधन के सही उपयोग को बाधित करती है और विकास की क्षमता को सीमित कर देती है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मानव पूंजी का अवमूल्यन होता है। शिक्षित और कुशल युवा या तो कम वेतन वाले असंगठित कार्यों में चले जाते हैं या शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिससे गाँवों में कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है। इससे कृषि, छोटे उद्योग और ग्रामीण उद्यमिता का विकास धीमा पड़ जाता है। लगातार बनी रहने वाली यह स्थिति देश में आर्थिक असमानता को बढ़ाती है और दीर्घकाल में संतुलित एवं समावेशी विकास को बाधित करती है।

परिणाम

ग्रामीण बेरोजगारी के परिणाम स्पष्ट रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। आर्थिक रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में आय की कमी और गरीब परिवारों की बढ़ती संख्या आर्थिक अस्थिरता पैदा करती है। 2025-26 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या लगभग 2.8 करोड़ है, जिसमें अधिकांश युवा श्रेणी (15-29 वर्ष) में आते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी बढ़ाती है, बल्कि स्थानीय बाजार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास दर को भी प्रभावित करती है। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से, बेरोजगारी के कारण निराशा, असंतोष और सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। बेरोजगार युवा शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं या शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे ग्रामीण समाज का संतुलन बिगड़ता है। राजनीतिक रूप से यह रोजगार-संबंधी नीतियों और सरकारी योजनाओं पर दबाव डालता है। अनुसंधान और रिपोर्टों के अनुसार, बेरोजगारी की अधिकता वाले जिलों में चुनावी मतदान पैटर्न में बदलाव और रोजगार केंद्रित मुद्दों का प्राथमिकता से उठना देखा गया

है। इस प्रकार, ग्रामीण बेरोजगारी के परिणाम व्यापक और बहुआयामी हैं, जो व्यक्तिगत जीवन, समाज और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करते हैं।

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने हेतु कुछ पहले भारत सरकार द्वारा- भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने हेतू विभिन्नर पहले व योजनाये लायी गई है जिससे ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी इनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को कौशल, आय और अवसर उपलब्ध कराना है। प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं–

I. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - यह योजना ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति-कार्य दिवस का रोजगार मिला। यह योजना विशेष रूप से गरीब और कृषि असंतुलित क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करती है।

II. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) - इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण देना है। ग्रामीण युवाओं को छोटे उद्योग, कृषि, सेवा और तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 2025-26 तक लगभग 12 लाख ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

III. डीडीयू-ग्रामोद्योग/सहकारी और लघु उद्योग योजनाएँ- ये योजनाएँ ग्रामीण लघु उद्योग, हस्तशिल्प और स्वरोजगार को बढ़ावा देती हैं। सरकार ने ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित किया।

IV. कृषि और सहायक रोजगार योजनाएँ- जैसे प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण योजना (PM-AASHA), कृषि निवेश ऋण योजना, जल संरक्षण और सिंचाई योजनाएँ। इन योजनाओं से ग्रामीण किसानों को आय बढ़ाने और कृषि आधारित रोजगार सृजन का अवसर मिलता है।

इन सभी पहलों का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, आर्थिक असमानता घटाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार पैदा होता है, बल्कि ग्रामीण युवा शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त कर पाते हैं।

समाधान और सुझाव

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत है जो निम्नवत है -

1. कृषि का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
2. सिंचाई सुविधाओं के विस्तार कर के सिंचित क्षेत्र को बढाया जाए।
3. जैविक खेती को बढावा दिया जाना चाहिए।
4. कृषि आधारित उद्योगों का विकास निरंतर किया जाये।
5. गांवों के आसपास खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाने चाहिए।
6. कुटीर उद्योगों की स्थापना किया जाना चाहिए जिससे मौसमी बेरोजगारी को दूर किया जा सके।
7. ग्रामीण शिक्षा प्रणाली में तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य रुप से लागू किया जाना चाहिए।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में सडक, बिजली, इंटरनेट, और बैकिंग जैसी सुविधओं का तेजी से विकास किया जाना चाहिए।
9. किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
10. प्रत्येक ब्लाक लेबल पर उद्योगों की स्थापना को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को केवल आय या रोजगार की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता; यह एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना और अवसरों की असमानता से भी गहराई से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित

संसाधन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, और आधुनिक कौशलों की कमी इस स्थिति को और जटिल बना देते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, निश्चित रूप से अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं। ये योजनाएँ रोजगार के अवसर पैदा करती हैं और लोगों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा देती हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं क्योंकि इनका प्रभाव अक्सर सीमित और अस्थायी होता है। स्थायी समाधान के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का व्यापक स्तर पर विविधीकरण किया जाए। इसका अर्थ है कि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी, मत्स्य पालन, और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए।

अंततः ग्रामीण विकास के लिए एक समावेशी और दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों–विशेषकर महिलाओं, दलितों और आदिवासियों–की भागीदारी सुनिश्चित हो। जब तक विकास के लाभ समाज के हर हिस्से तक समान रूप से नहीं पहुँचते तब तक वास्तविक और स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है।

संदर्भ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - रमेश सिंह 2023
2. नीति आयोग की रिपोर्ट (भारत सरकार) 2024-25
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत सरकार।
4. विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय लेख।
5. भारतीय अर्थव्य वस्थात रुद्र एवं सुंदरम हिमालय पब्लिकेशन नई दिल्ली ।
6. भारतीय अर्थव्य वस्थात एम.एल.झिंगन।

सरकारी रिपोर्ट एवं सर्वे

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार।

2. नीति आयोग की प्रमुख रिर्पोट।
3. भारत सरकार की गरीबी से संबंधित रिपोर्ट।
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय की संबंधित रिपोर्ट।
5. मनरेगा से संबंधित आंकड़े और रिपोर्ट।
6. Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
7. Jean Drèze, & Amartya Sen. (2013). *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions*. Princeton University Press.
8. Economic and Political Weekly (EPW). (Various Issues). Articles on rural unemployment and poverty in India.
9. Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). (2023). *Unemployment Data Reports*. Mumbai: CMIE.